Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

21 अगस्त 2019
नई दिल्ली

देश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बात करने दें:

आरक्षण पर खुली बहस के आरएसएस के मंसूबे पर पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन ने जताई आपत्ति

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने आरक्षण के विषय पर विभिन्न समुदायों के बीच 'शांतिप्रीय चर्चा' के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्ताव पर सवाल उठाया है। चेयरमैन ने कहा कि दलितों और ओबीसी को प्राप्त कम्युनिटी कोटा आरक्षण नहीं, बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संवैधानिक मांग पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

आरक्षण पर बात–चीत को लेकर आरएसएस प्रमुख के हालिया बयान में कोई नई बात नहीं है। बल्कि यह उच्च जाति की आरक्षण विरोधी साज़िश का हिस्सा है जिसे आरएसएस और बीजेपी शुरू से ही बढ़ावा देती रही हैं। इसे भागवत और आरएसएस द्वारा आरक्षण के ख़िलाफ पूर्व में दिये गए बयानों के आधार पर देखना चाहिए। अभी कुछ ही महीनों पहले बीजेपी ने आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत कोटा देकर आरक्षण के असल उद्देश्य को ही कमज़ोर कर दिया है। भारत के बारे में संघ परिवार की सोच बस इतनी है कि जाति व्यवस्था पर क़ायम उस सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे को फिर से लागू किया जाए, जिसमें नेतृत्व केवल ब्राह्मणों के हाथ में होगा और अछूत और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के रास्ते बंद हो जाएंगे।

संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आरक्षण का मकसद सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों और शिक्षा के मैदान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। कई जांच और अध्ययनों से यह पता चलता है कि एससी–एसटी और ओबीसी वर्गों और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का ने केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में, बल्कि सत्ता के हर मैदान में अपनी आबादी से बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि अगर इन वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, तो उन्हें कोटा आरक्षण जैसे किसी उपकार की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने मोहन भागवत को इस तरीके पर अमल करते हुए आरएसएस, बीजेपी और दूसरे मोदी मंत्रीमंडल की उच्च इकाईयों का नए सिरे से गठन करने की राय दी।

ई. अबूबकर ने दलित और पिछड़े वर्गों के समूहों, पार्टियों और नेताओं से अपील की कि वे यह बात साफ कर दें कि जब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व का संवैधानिक मकसद हासिल नहीं होता, आरक्षण के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

डॉ मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली